शारधम्मा और अन्य।

बनाम

उप आयुक्त और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 5689 /2025)

29 अप्रैल 2025

[बी.वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सहायक आयुक्त के साथ-साथ उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने के कारण उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और दिनांक 18.12.2003 के आदेश के माध्यम से, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान अपीलकर्ताओं ने इस मामले में एक रिट अपील दायर की और इसे भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।

शीर्ष टिप्पणियां

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978 - धारा 5 - वर्ष 1946-47 में अपीलकर्ताओं के स्वामित्वधारी पूर्ववर्ती आर को एक भूमि बेच दी गई थी और 12.05.1954 को एक सगुवल्ली चिट की पुष्टि की गई थी - भूमि को आर द्वारा 20.06.1969 को बेच दिया गया था - पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन 06.06.1992 को एक डी (मूल अनुदानग्राही का कानूनी प्रतिनिधि नहीं) द्वारा दायर किया गया था - सहायक आयुक्त ने आवेदन की अनुमति दे दी है दिनांक 01.03.1999 के आदेश के माध्यम से और अपील पर, उपायुक्त ने दिनांक 16.10.2003 के आदेश के माध्यम से पूर्वोक्त आदेश की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया है कि मैसूर भूमि राजस्व नियमों के तहत हस्तांतरण खंड का उल्लंघन हुआ था, जो अनुदान की तारीख को लागू थे, विशेष रूप से गैर-हस्तांतरण खंड के कारण, भूमि को 20 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था - रिट याचिका और उसके बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट अपील को खारिज कर दिया गया:

अभिनिर्धारित: पीटीसीएल अधिनियम के तहत मामले में दाखिल आवेदन निराशाजनक रूप से बिलम्ब और लापरवाही के कारण बाधित था - वर्तमान मामले में, आवेदन को केवल 06.06.1992 को प्राथमिकता दी गई थी और भूमि 20.06.1969 को बेची गई थी, यह निश्चित रूप से उचित अवधि से परे थी और इसलिए, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है -

अपीलकर्ताओं ने बिक्री विलेख के तहत, जमीन खरीदी थी

---

*रचयिता

और, इसलिए, विचाराधीन भूमि पर सभी अधिकार हैं - पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को 10 साल से अधिक की अवधि की समाप्ति के बाद दाखिल किया गया था, इसे देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था - सगुवल्ली चिट के संबंध में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी पुष्टि 12.05.1954 को की गई थी - रिकॉर्ड से पता चलता है कि एक गैर-हस्तांतरण खंड है जो प्रदान करता है कि प्रश्नगत भूमि को 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और इसलिए, सगुवल्ली चिट में इस स्पष्ट पाठ के आलोक में, मामले में निष्पादित बिक्री विलेख को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था जैसा कि अधिकारियों द्वारा किया गया है और नीचे के न्यायालयों द्वारा पुष्टि की गई है - इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों के पास भी इस मामले में कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे मूल अनुदान ग्राही आर के वंशज नहीं हैं और, इसलिए, वे पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन को दाखिल नहीं कर सकते थे - इस प्रकार, आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। [पैरा 6-10]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

नेक्कंटी राम लक्ष्मी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **(2020) 14 एससीसी 232;** *विवेक एम. हिंदुजा और अन्य बनाम एम. अश्वथा और अन्य* **(2020) 14 एससीसी 228 - का उल्लेख किया गया।**

अधिनियमों की सूची

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978; मैसूर भू-राजस्व नियम।

प्रमुख शब्दों की सूची

कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978 की धारा 5; देरी और लापरवाही ; गैर-हस्तांतरण खंड; उचित अवधि से परे।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5689/2025

डब्ल्यू ए संख्या 1928/2004 में कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु के दिनांक 27.07.2010 के निर्णय और आदेश से

अधिवक्तागण

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता :

सुश्री किरण सूरी, वरिष्ट अधिवक्ता, एसजे अमित, सुश्री विदुषी गर्ग, डॉ. श्रीमती विपिन गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता :

पी. विश्वनाथ शेट्टी, वरिष्ट अधिवक्ता, वी. एन. रघुपति, राघवेंद्र एम. कुलकर्णी, सुश्री. मिथिली एस, एम. बंगारस्वामी, वेंकट रघु मन्नेपल्ली, धनेश इश्धन, शिव कुमार, सुश्री वैष्णवी, जीएन रेड्डी, महेश ठाकुर, विभव चतुर्वेदी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय बैंगलोर

द्वारा रिट अपील संख्या 1928/2004 (एससी/एसटी) में पारित दिनांक 27.07.2010 के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 50446/2003 दिनांक 18.12.2003 में पारित आदेश को रद्द कर दिया है।

3. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि होसहल्ली गांव, हुलिकुंटे होबली के पुराने सर्वे नंबर 14/1 (नया संख्या 150) में चार एकड़ जमीन संपादक तहसीलदार,सीरा तालुक द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से श्री रंगा उर्फ़ रंगप्पा को पट्टे पर दी गई थी।वर्ष 1946-47 में यानी 01.04.1946 और उनके पक्ष में 12.05.1954 को एक सगुवल्ली चिट की पुष्टि की गई। श्री रंगा द्वारा भूमि के लिए अपसेट(प्ररक्षित) कीमत का भुगतान किया गया था और श्री रंगा 1946 से 1969 तक, अर्थात् 23 वर्षों की अवधि के लिए प्रश्नगत भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे और

उपभोग में बने रहे। राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम अस्तित्व में रहा। श्री रंगा, भूमि धारक (अनुदानग्राही) ने पहले अपीलकर्ता के पति को जमीन बेच दी, अर्थात्, श्री बसवराजप्पा को एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से और अपीलकर्ता नंबर 2 बसवराजप्पा का बेटा है। इस प्रकार, विचाराधीन भूमि स्वर्गीय श्री रंगा और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और पुत्र के नाम पर कब्जे में रही।

4. 06.06.1992 को, डोड्डा हनुमैया ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमि के हस्तांतरण का निषेध) अधिनियम, 1978 (इसके बाद 'पीटीसीएल अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 5 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि मूल अनुदानग्राही अपने दिवंगत पिता का बड़ा भाई है और जमीन 20.06.1969 को बेच दी गई थी और चूंकि जमीन 20.06.1969 को बेची गई थी, उसी का कब्जा मूल अनुदानग्राही को और चूंकि मूल अनुदानग्राही जीवित नहीं था, उसके रिश्तेदार को वापस किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना उचित है कि उत्तरदाता संख्या 3 डोड्डाहनुमैया निश्चित रूप से मूल अनुदानग्राही का कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। सहायक आयुक्त ने दिनांक 01.03.1999 के आदेश के तहत आवेदन की अनुमति दी है और अपील पर, उपायुक्त ने दिनांक 16.10.2003 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त आदेश की पुष्टि की है

मैसूर भू-राजस्व नियमावली के अंतर्गत अंतरण खंड का उल्लंघन हुआ था,

जो अनुदान की तारीख को लागू थे, विशेष रूप से गैर-हस्तांतरण खंड के कारण, भूमि को 20 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरित नहीं किया जा सकता था। वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सहायक आयुक्त के साथ-साथ उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और दिनांक 18.12.2003 के आदेश के माध्यम से, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

5 इसके बाद वर्तमान अपीलकर्ताओं ने इस मामले में एक रिट अपील दायर की और इसे कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2010 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

6 इस न्यायालय ने सहायक आयुक्त, उपायुक्त, कर्णाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। वर्तमान मामले में, भूमि को वर्ष 1946-47 में अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती श्री रंगा को बेच दिया गया था और 12.05.1954 को एक सगुवल्ली चिट की पुष्टि की गई थी। भूमि को श्री रंगा द्वारा 20.06.1969 को बेचा गया था और पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन 06.06.1992 को दायर किया गया था। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पीटीसीएल अधिनियम के तहत मामले में प्राथमिकता दिए गए आवेदन देरी और लापरवाही से निराशाजनक रूप से वर्जित था, जैसा कि ***नेकांति रमा लक्ष्मी बनाम*** कर्णाटक ***राज्य*** और अन्य (2020) 14 उच्चतम न्यायालय वाद ***232 के मामले में आयोजित किया गया है***

पैराग्राफ 7 और 8 में निम्नानुसार हैं:

"7. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री आर.एस. हेगड़े ने कई आधारों का आग्रह किया। श्री हेगड़े द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भूमि के पहले खरीदार के गैर-जोइंडर के लिए कार्यवाही शून्य है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि गैर-हस्तांतरण अवधि यानी जिस अवधि के लिए क्रिअप्पा भूमि को हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, वह 15 वर्ष नहीं थी, बल्कि भूमि के नियमों के तहत 10 वर्ष थी और इसलिए, हस्तांतरण 10 साल बाद वैध बनाया गया था। हालांकि, आवेदक ने मूल अनुदान प्रस्तुत नहीं किया था, और इसलिए, उद्देश्य के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं था कि हस्तांतरण गैर-अलगाव अवधि का उल्लंघन था। हालाँकि, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए बिंदुओं में से एक स्वीकृति का पात्र है। वह मुद्दा यह है कि भूमि की बहाली के लिए आवेदन क्रिअप्पा के उत्तराधिकारी द्वारा अनुचित रूप से लंबी अवधि के बाद किया गया था
यानी अधिनियम के लागू होने से 25 साल। अधिनियम की धारा 4 का ही इसमें सर्वव्यापी प्रभाव है, जो "अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में की गई स्वीकृत भूमि के हस्तांतरण" को अमान्य और शून्य मानकर रद्द कर देता है। अधिनियम में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि अधिनियम के लागू होने से कितना पहले था। इस प्रकार, अधिनियम के एक स्पष्ट और आलोचनात्मक पढ़ने पर, ऐसा लगता है कि यह अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले समय पर की गई कार्यवाही को कवर करता है। हालांकि, हमें इस प्रावधान की औचित्य से निपटने के लिए नहीं कहा गया है और हम इस पर कुछ भी कहने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा इस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा गया है।
(मांचेगौड़ा बनाम कर्णाटक राज्य, (1984) 3 एससीसी 301।

"8. हालांकि, जो प्रश्न उठता है वह अधिनियम की धारा 5 की शर्तों के संबंध में है जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थानांतरण को शून्य के रूप में रद्द करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। यह धारा किसी भी अवधि को निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर ऐसा आवेदन किया जा सकता है। न ही यह उस अवधि को निर्धारित करता है जिसके भीतर स्वत: कार्रवाई की जा सकती है। छेदी लाल यादव बनाम हरि किशोर यादव [छेदी लाल यादव बनाम हरि किशोर यादव, (2018) 12 एससीसी में यह न्यायालय

527:(2018) 5 एससीसी (सीआईवी) 427] और निंगप्पा बनाम कॉमर में भी। [निंगप्पा बनाम कॉमर। (2020) 14 एससीसी 236] ने कानून में एक स्थापित स्थिति को दोहराया कि क्या क़ानून सीमा की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, क़ानून के प्रावधानों को उचित समय के भीतर लागू किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि कार्रवाई चाहे पार्टियों के आवेदन पर, या स्वत: चलती हो, उचित समय के भीतर की जानी चाहिए। यह कार्रवाई एक समान अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुई, जिसमें किसानों को कुछ भूमि की बहाली का प्रावधान किया गया था, जिन्हें किराए के बकाया के लिए बेचा गया था या जहां से उन्हें 1-1-1939 से 31-12-1950 तक भूमि के बकाया के लिए बेदखल कर दिया गया था। कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण किसानों को यह राहत दी गई थी, जिससे कृषि कार्य असंभव हो गया था। बहाली के लिए आवेदन 24 साल बाद किया गया था और अनुमति दी गई थी। यह उस पृष्ठभूमि में है कि इस न्यायालय ने कहा कि ऐसा करना अनुचित था। हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि प्रतिवादी राजप्पा द्वारा भूमि की बहाली के लिए किया गया वर्तमान आवेदन अनुचित रूप से लंबी अवधि के बाद किया गया था और उस आधार पर खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय, अर्थात् आर. रुद्रप्पा बनाम कॉमर। [आर.रुद्रप्पा बनाम कॉमर., 1998 एससीसी ऑनलाइन कर 671:(2000) 1 कांत एलजे523], मद्दुरप्पा

बनाम राज्य (कर्णाटक) मारेगौदव। कॉमर। [जी. मारेगौड़ा बनाम कॉमर, (2000) 2 कांट एलजे एसएन 4बी] यह मानते हुए कि अधिनियम की धारा 5 द्वारा कोई सीमा प्रदान नहीं की गई है और इसलिए, किसी भी समय एक आवेदन किया जा सकता है, इसे खारिज कर दिया जाता है। तदनुसार आदेश दें।"

7 उपरोक्त निर्णय के आलोक में, जैसा कि वर्तमान मामले में, आवेदन को केवल 06.06.1992 को प्राथमिकता दी गई थी और भूमि 20.06.1969 को बेची गई थी, यह निश्चित रूप से उचित अवधि से परे थी और इसलिए, सहायक आयुक्त, उपायुक्त, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ताओं ने बिक्री विलेख के आधार पर भूमि खरीदी थी, और इसलिए, विचाराधीन भूमि पर उनका पूरा अधिकार है।

विवेक *एम. हिंदुजा और अन्य बनाम एम. अश्वथ और अन्य*

(2020) 14 सुप्रीम कोर्ट के मामले 228 के मामले में फिर से यह अदालत द्वारा समान अधिनियम से निपटते हुए, पैरा 10 से 12 में, निम्नानुसार आयोजित किया है:

"10. पुणे नगर निगम v. महाराष्ट्र राज्य [पुणे नगर निगम बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 5 एससीसी 211] में इस न्यायालय ने सीमा की अवधि से परे आदेशों को अमान्य घोषित करने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत किया: (एससीसी पी. 226, पैरा 39)

"39. सभी न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री को रद्द करते हुए और कई मामलों का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि यदि आदेश की अमान्यता से व्यथित पक्ष यह घोषणा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखता है कि उसके खिलाफ आदेश निष्क्रिय था, उसे सीमा द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अदालत के समक्ष आना होगा। "यदि सीमा का

वैधानिक समय समाप्त हो जाता है, तो अदालत मांगी गई घोषणा नहीं दे सकती है।

(जोर दिया गया)

"11. हम उपरोक्त टिप्पणियों के साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। हालांकि, यह जोड़ना आवश्यक है कि जहां सीमा निर्धारित नहीं है, पार्टी को उचित समय के भीतर सक्षम अदालत या प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए, जिसके बाद कोई राहत नहीं दी जा सकती है। जैसा कि पहले तय किया गया था, यह सिद्धांत स्वत: संज्ञान लेने वाली कार्रवाइयों पर भी लागू होगा।

"12. हम आक्षेपित निर्णयों से पाते हैं [विवेक एम. हिंदुजा बनाम एम. अश्वथा, 2006 एससीसी ऑनलाइन कर 882] , [जॉर्ज थॉमस बनाम के.पी. कृष्णप्पा, 2011 एससीसी ऑनलाइन कर 4496] कि उच्च न्यायालय ने उस अवधि का उचित सम्मान नहीं दिया है जिसके भीतर वर्तमान मामलों में कार्रवाई की गई थी। इन सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारियों ने उत्तरदाताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था और तबादलों को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

8 उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात के आलोक में, यह सुरक्षित रूप से एकत्र किया जा सकता है कि चूंकि पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को 10 वर्ष से अधिक की अवधि की समाप्ति के बाद प्राथमिकता दी गई थी, इसलिए इसे देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

9 सगुवल्ली चिट के संबंध में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी पुष्टि 12.05.1954 को की गई थी।

स्थानीय भाषा के संस्करण और अंग्रेजी अनुवाद जो रिकॉर्ड पर हैं, से पता चलता है कि एक गैर-अलगाव खंड है जो प्रदान करता है कि विचाराधीन भूमि को 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और इसलिए, सगुवल्ली चिट में इस स्पष्ट पाठ के आलोक में, मामले में निष्पादित बिक्री विलेख को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था जैसा कि प्राधिकारियों द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि नीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा की गई है।

10 परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। इस न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओ के पास भी इस मामले में कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे मूल अनुदानग्राही श्री रंगा के वंशज नहीं हैं और इसलिए, वे पीटीसीएल अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को प्राथमिकता नहीं दे सकते थे। इस कारण से भी, आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।

11 अपील की अनुमति दी जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

शीर्ष टिप्पणियां : अंकित ज्ञान द्वारा तैयार की गयी

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया ।